



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ ज्येष्ठ 5, 1938

No. 230]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**अधिसूचना**

मुंबई, 20 मई, 2016

सं. टीएएमपी/04/2004-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 11 मई, 2016 के पत्र क्रमांक 8(15)/2015-टीएएमपी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुपालनात्मक कार्रवाई के रूप में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 के आदेश क्रमांक टीएएमपी/4/2004-सामान्य को अस्थायी रूप से प्रास्थगित करता है और अपने पहले के दिनांक 12 जनवरी, 2005 और 15 मार्च, 2005 के आदेश क्रमांक टीएएमपी/04/2004 को पुनः स्थापना करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**केस सं टीएएमपी/04/2004-सामान्य****आदेश****(मई, 2016 के 19 वाँ दिन पारित)**

एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 11 मई 2016 के पत्र क्रमांक 8/(15)2015-टीएएमपी द्वारा लिये गये निर्णय को सूचित किया है कि एमओएस द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17 सितंबर, 2015 के पत्र क्रमांक 8/(15)2015-टीएएमपी को अगले आदेश जारी होने तक अस्थायी रूप से प्रास्थगित किया जाए और अपने पत्र दिनांक 1/3 जनवरी, 2005 और 9 मार्च 2005 के पत्र सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी द्वारा सूचित नीति दिशा-निर्देश को पुनः स्थापना किया जाए। एमओएस के दिनांक 11 मई, 2016 के पत्राचार में निम्नलिखित रूप से वर्णित किया गया है:—

- (i). चूँकि इस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 17 सितंबर, 2015 के पत्र क्रमांक 8/(15)2015-टीएएमपी के संशोधन अनुदेश के अंतर्गत प्रशुल्क पुनः विवरण तीव्र रूप से ऊपर बढ़ेगा, जो कि कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने की मंत्रालय के मंशा के प्रतिकूल है। वास्तव में, कोस्टल शिपिंग/ओपरेशन्स के लेन-देन भी संपूर्ण रूप से

भारतीय रुपयों में होते हैं और प्रशुल्क भारतीय रुपयों में वसूल किये जाते हैं। अमेरिकी डॉलर में प्रशुल्क वसूली करने की आवश्यकता को पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है।

भारतीय रुपयों के साथ अमेरिकी डॉलर के विनिमय दर को लिंक करने के परिणामस्वरूप प्रशुल्क में उतार-चढ़ाव को तटीय प्रशुल्क की पुनः विवरण पूर्णरूप से समाधान करने की आवश्यकता है। जिससे कि तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- (ii). तदनुसार, उस समय तक इन वाद विषयों का समाधान हो जाना चाहिए। एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 17 सितंबर, 2015 द्वारा अपने निर्णय, अगले आदेश जारी होने तक मंत्रालय के अनुदेशों को अस्थायी रूप से प्रास्थगित करने के लिए और (तत्कालिक) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 1/3 जनवरी, 2005 और 9 मार्च, 2005 के अनुदेशों को पुनःस्थापना करने के लिए सूचित किया है।

2. उपरोक्त परिदृश्य के मद्देनजर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के धारा 42(3) के अंतर्गत सभी महापत्तन न्यासों और प्राधिकृत प्राइवेट ओपरेटरों के लिए एमओएस ने इस प्राधिकरण को तटीय कार्गो/कन्टेनरों/वेसेल्स से संबंधित प्रभारों को समुचित रूप से निर्धारित करने के लिए निर्देश दिया है।

3. एमओएस द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर, यह प्राधिकरण दिनांक 17 सितंबर, 2015 के पत्र क्रमांक 8/(15)2015-टीएएमपी, एमओएस द्वारा जारी निर्देश के आधार पर पारित आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 के आदेश क्रमांक टीएएमपी/4/2004-सामान्य को अस्थायी रूप से एमओएस से अगला आदेश आने तक प्रास्थगित करता है। परिणामस्वरूप, एमओएस द्वारा यथा निर्देशित दिनांक 7 जनवरी, 2005 के आदेश सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य और दिनांक 1 जनवरी, 2005 के (तत्कालिक) एमएसआरटीएच द्वारा जारी नीति दिशा-निर्देश के आधार पर दिनांक 15 मार्च 2005 के कथित संशोधित आदेश को पुनः स्थापित किया जाता है।

4. तदनुसार, सभी महापत्तन न्यासों को अपने दरमानों में संशोधन करने के लिए निर्देश दिया जाता है। महापत्तन न्यासों पर संचालित प्राइवेट टर्मिनल ओपरेटरों के केस में, उनके प्रचलित एसओआर में, विदेशी वर्ग के वेसेल्स से संबंधित प्रभारों/और/ अथवा कन्टेनर से संबंधित प्रभारों को अमेरिकी डॉलर में मूल्य अंकित करेंगे। तदनुसार, अपने दरमानों में संशोधन करने के लिए निर्देश दिया जाता है।

5. एमओएस के निर्देश के आधार पर, इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभाव में आयेगा।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन— III / 4 / असा. / 143 / 16(103)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th May, 2016

No. TAMP/4/2004/Genl.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby keeps the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 5 October 2015 temporarily in abeyance and restore its earlier Order No.TAMP/4/2004-Genl. Dated 12 January 2005 and 15 March 2005 in pursuance of the direction issued by the Ministry of Shipping vide its letter no. 8(15)/2015-TAMP dated 11 May 2016 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/4/2004-Genl.

ORDER

(Passed on this 19th day of May 2016)

The MOS vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 11 May 2016 has decided to temporarily keep the earlier direction issued by the MOS vide its letter no.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 in abeyance

till further orders and restore the policy direction issued by the (then) MSRTH vide its letter No.PR-14019/29/2001-PG dated 1st/3rd January 2005 and 9 March 2005. In the communication dated 11 May 2016 the MOS, has stated the following:

- (i). Since restatement of tariff under the amended instruction issued vide this Ministry's letter No.8(15)/2015-TAMP dated 17 September 2015 has had the effect of sharply raising the tariff and would be contrary to the Ministry's desire to promote coastal shipping, and also the fact that transaction in coastal shipping/ operations are entirely domestic and the tariff is collected in rupees, the need to link the tariff to US \$ needed to be reviewed.

The consequences related with linkage of exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-à-vis US \$ for restatement of coastal tariff need to be addressed at length so that there is no adverse impact on the promotion of coastal shipping.

- (ii). Accordingly, till such time these issues are addressed, it has been decided by the MOS to temporarily keep the instructions issued in this Ministry's letter of even no dated 17 September 2015 in abeyance till further orders and restore the instructions contained in the then Ministry of Shipping, Road Transport & Highways letters No.PR-14019/29/2001-PG dated 1st / 3rd January 2005 and 9 March 2005.

2. In view of the above, the MOS has directed this Authority to appropriately prescribe the **coastal cargo**/ container/ vessel related charges levied at all Major Port Trusts and private operators authorized under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963 immediately.

3. In view of the above direction issued by the MOS, this Authority keeps the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 5 October 2015 passed by this Authority based on the direction issued by the MOS vide its letter No. 8(15)/2015-TAMP dated 17 September 2015 temporarily in abeyance till further orders from the MOS. Consequently, the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 7 January 2005 and the amendment to the said Order dated 15 March 2005 based on the policy direction issued by the (then) MSRTH dated 1 January 2005 are restored as directed by the MOS.

4. All the Major Port Trusts are directed to amend their Scale of Rates accordingly. In the case of private terminal operators operating in the Major Port Trusts in whose existing SOR the vessel related charges and/ or container related charges for foreign category are denominated in US dollar terms, they are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

5. The order passed by this Authority based on the direction of the MOS shall come into effect from the date of notification of the order in the Gazette of India.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(103)]